पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International 1983 2012

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 13, अंक 4/2012

... बढ़ता जा रहा है विद्युत घाटा

आज बिजली के बिना जीवन मुश्किल है। यह हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। राज्य सरकारों के अधीन परिचालित विद्युत कंपनियां अपने कमजोर प्रबंधन व स्थानीय सरकारों की चुनावी राजनीति के चलते काफी आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। जिसका मुख्य कारण विद्युत की उत्पादन लागत से कम वसूली होना है। राजस्थान में तो लागत की 45 प्रतिशत राशि ही वसूली जा रही है, जिससे 55 फीसदी घाटा हो रहा है। कंपनियों का प्रबंधन सही नहीं होने से बिजली चोरी और विद्युत छीजत भी सबसे बड़ी समस्या है। अन्ततोगत्वा इनका भार उपभोक्ता को भुगतना होता है।

बिजली दरें बढ़ाए जाने के बावजूद अभी भी प्रदेश की बिजली कंपनियों पर 38 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है, जिस पर करीब चार हजार करोड़ रुपए ब्याज देना पड़ता है। बिजली कंपनियों की मानें तो औसतन पांच रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से ही राजस्व मिल रहा है, जबकि बिजली सात रुपए प्रति यूनिट पड़ रही है। इससे साफ जाहिर है कि उपभोक्ता को बिजली के लिए अपनी जेब और ढ़ीली करनी होगी। हालांकि केन्द्र सरकार की वित्तीय पुनः संरचना में तीन साल में बिजली कंपनियों को अनुदान देकर घाटे से उबारने की भी शर्त है।

प्रदेश में ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों की ओर अधिक ध्यान देना होगा। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं। इसके लिए निजी क्षेत्र को भी पॉवर प्लांट्स लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे प्रतिस्पर्धा को बल मिलेगा तथा उत्पादन लागत में कमी आ सकती है। उपभोक्ता को बिजली उचित दरों पर मिले, ऐसी व्यवस्था अपेक्षित है।

बिजली उत्पादन बढ़ाने, प्रबन्धन व वितरण व्यवस्था में सुधारों के साथ-साथ बिजली के सदुपयोग पर ध्यान देना होगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को जागरूक करने के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है।

इस अंक में...

- बच्चों का हलवा खा गए अफसर 4
- जब्त होगी लोकसेवकों की काली कमाई 6
- मरीजों की सामान्य जांचें होंगी मुफ्त 7
- देश में 30 फीसदी बचा भूजल भंडार 9
- जमीनी स्तर तक जागा पूरा देश 10

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया से अभी भी अनजान

प्रदेश में 12 जिलों के 68 फीसदी उपभोक्ताओं का मानना है कि मीटर तेज चलने के कारण उनके बिजली बिल ज्यादा आ रहे हैं। वहीं 66 फीसदी उपभोक्ताओं का कहना है कि अधिक वोल्टेज के चलते बिजली के उपकरण खराब हो जाते हैं। बिजली सुधार कार्यक्रमों के बावजूद आज भी 75 फीसदी उपभोक्ता विद्युत आपूर्ति की समस्या से परेशान हैं तथा 59 फीसदी उपभोक्ता सेवा प्रदाताओं द्वारा स्थापित शिकायत निवारण प्रक्रिया से अनजान हैं।

कट्स द्वारा प्रदेश के 12 जिलों में संचालित ग्रेनिका परियोजना के तहत किए गए सर्वेक्षण से सामने आई इस सच्चाई को 30 अक्टूबर 2012 को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय मीडिया कार्यशाला में प्रस्तुत किया गया। कट्स के वरिष्ठ कार्यक्रम समन्वयक दीपक सक्सेना ने 'राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की स्थिति' पर करवाए गए सर्वे से प्राप्त तथ्यों की जानकारी देते हुए बताया कि सर्वेक्षण में चयनित 12 जिलों के 2419 विद्युत उपभोक्ताओं से साक्षात्कार किया गया जिसमें करीब 25 फीसदी महिलाएं थीं।

इस अवसर पर राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के पूर्व अध्यक्ष पी.एन. भंडारी ने कहा कि विद्युत क्षेत्र देश की प्रगति का आधार है। उपभोक्ता बिजली की काफी शिकायतें करते हैं। उनके निराकरण की भी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को इनकी पूरी जानकारी नहीं है। विद्युत चोरी और छीजत पर नियंत्रण भी आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि कृषि क्षेत्र में छोटे किसानों को ही सब्सिडी दी जाए, बड़े किसानों को यह लाभ नहीं मिलना चाहिए।

कार्यशाला में गोपाल शर्मा, अतिरिक्त निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय ने अपने सम्बोधन में कहा कि उपभोक्ताओं के सामने बिजली की कई समस्याएं हैं, उनके निराकरण के लिए उपभोक्ता को स्वयं जागरूक व सजग रहना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की स्थिति पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया गया।

कार्यक्रम में कट्स के निदेशक जार्ज चेरियन ने बताया कि ग्रेनिका परियोजना का खास मकसद उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण व स्वयंसेवी संगठनों की कार्यक्षमता को बढ़ाना है। कार्यशाला में वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र बोडा, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के संयुक्त सचिव आर.सी.शर्मा, नफा नुकसान के मुख्य सम्पादक जयसिंह कोठारी, राजस्थान पत्रिका से विमल जैन, सहित राज्य में चयनित 12 जिलों के परियोजना साझेदारों के साथ-साथ प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियों व राज्य सरकार के विद्युत विभाग व विद्युत नियामक आयोग के अधिकारियों ने भी अपनी सक्रिय भागीदारी दी।

राज्य में है उपभोक्ता जागरूकता और शिक्षा की सतत आवश्यकता

कट्स द्वारा राजस्थान के 12 जिलों में संचालित ग्रेनिर्का परियोजना के तहत 20 दिसम्बर, 2012 को जयपुर में राज्य स्तरीय फीडबैक राऊंड टेबल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र बोडा ने आज के दौर में उपभोक्ता को और अधिक जागरूक और सजग रहने की आवश्यकता जताते हुए कहा कि उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन होता रहना चाहिए।

कार्यक्रम में विधिक बाट व माप विभाग के संयुक्त निदेशक, पी.एन.पांडे ने प्रदेश में बाट-माप निरीक्षकों की कमी बताते हुए कहा कि उपभोक्ता बाट-माप से संबंधित शिकायतों की विभाग को जानकारी देकर सहयोग करें। अतिरिक्त जिला रसद अधिकारी लियाकत अली ने प्रशासन द्वारा चलाए गए 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान में विभाग द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। विद्युत लोकपाल डी.आर.माथुर ने संभागियों को बिजली संबंधी शिकायत निवारण प्रक्रिया के लिए बनाए गए विद्युत लोकपाल की कार्यप्रणाली के बारे में बताया।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में कट्स के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए ग्रेनिर्का परियोजना की तीन वर्षों की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परियोजना के तहत राज्य में उपभोक्ताओं की स्थिति व विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ताओं की स्थिति का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सरकार के साथ पैरवी भी की गई, जिसके कई सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। परियोजना समन्वयक अमरजीत सिंह ने परियोजना के तहत की गई तीन वर्ष की गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण किया।

कार्यक्रम में भारतीय मानक ब्यूरो के अतिरिक्त निदेशक शिव प्रसाद गुडे, जिला रसद कार्यालय, जयपुर के प्रवर्तन अधिकारी कुशाल बिलाला एवं नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर के प्रोफेसर डॉ. अशोक आर.पाटिल ने भी अपने विचारों एवं अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम में राज्य के 33 जिलों से स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों व मीडिया प्रतिनिधियों सहित 100 से भी ज्यादा संभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

'माई सिटी' परियोजना का शुभारम्भ

कट्स द्वारा एशिया फाउण्डेशन के सहयोग से माई सिटी परियोजना का 31 अक्टूबर, 2012 को शुभारम्भ किया गया, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों की सेवा वितरण प्रणाली में भागीदारी बढ़ाकर स्थानीय निकायों की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

परियोजना की शुभारम्भ बैठक को सम्बोधित करते हुए जयपुर नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगरूप सिंह यादव ने कहा कि हम लोग जयपुर शहर के 50 लाख से ज्यादा नागरिकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। हमारी जिम्मेदारी की सूची भी काफी लंबी है। माई सिटी परियोजना गतिविधियों से निगम को निश्चित तौर पर फायदा होगा।

बैठक में राज्य शहरीकरण आयोग के अध्यक्ष के.के.भटनागर, विशेष अतिथि ने परियोजना में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु किए जा रहे कट्स के प्रयासों की सराहना करते हुए सुझाव दिया कि वार्ड स्तर पर सड़क, सीवरेज व ठोसकचरा जैसी समस्याओं का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण किया जाए और सुधार के लिए नागरिकों के सुझाव लिए जाने चाहिए। संसाधनों का संग्रहण और उनका सही उपयोग अच्छी सेवा आपूर्ति के लिए आवश्यक है।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में कट्स के निदेशक जार्ज चेरियन ने स्थानीय सरकारों के महत्व और कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 74 वें संशोधन के अन्तर्गत शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के द्वारा आमजन तक शक्तियों के हस्तान्तरण से स्थानीय स्व-शासन मजबूत होगा। कट्स नगर निगम के किए कार्यों का फीडबैक लेकर व जनता के बीच समस्याओं का सर्वेक्षण कर सिटीजन रिपोर्ट कार्ड और लोक सेवा सूचकांक तैयार करेगा।

'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार से किया सम्मानित

'कट्स' द्वारा वर्ष 2002 से हर साल ग्रामीण पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के मकसद से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किए जाते रहे हैं। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उन पत्रकारों को दिए जाते हैं, जिन्होंने जनहित के मामलों को पत्रकारिता के माध्यम से असरदार तरीके से उठाया है।

इस बार का यह पुरस्कार 30 अक्टूबर 2012 को 'कट्स' द्वारा ग्रेनिर्का परियोजना के तहत जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय मीडिया कार्यशाला के दौरान गोपाल शर्मा, सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार के कर कमलों द्वारा प्रदान किया गया।

उन्होंने वर्ष 2011 के लिए चयनित 'खाद्य सुरक्षा' विषय पर की गई उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए बाड़मेर जिले के पनावड़ा गांव निवासी स्वतंत्र पत्रकार चूना राम गोदारा को पुरस्कार स्वरूप 10 हजार रुपए की राशि का चैक एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर 'ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार' से सम्मानित किया।

राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का सपना अधूरा

केन्द्र सरकार की योजना के तहत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का सपना अभी भी कोसों दूर है। ग्रामीण इलाकों तक आईटी की सुविधा देने और पंचायत स्तर से जुड़े सभी कार्य एक ही छत के नीचे लाने के मकसद से हर ग्राम पंचायत में यह केन्द्र चालू किए जाने थे।

जयपुर जिले में इन केन्द्रों की स्थापना के लिए 450 भवन तो बनाए गए, लेकिन अभी तक जनता के एक भी काम नहीं आया। अधिकांश भवनों पर ताले जड़े हैं या सरपंच व सचिव नए भवन होने के नाते उनमें बैठे हैं। भवनों का मकसद पूरा होने से जुड़े सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं है।

इन केन्द्रों पर इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिए जाने थे और कम्प्यूटर स्टाफ की भर्ती होनी थी, लेकिन सब ठंडे बस्ते में है। केन्द्र चलाने को लेकर मॉनिटरिंग का न होना और अफसरों की जिम्मेदारी ढंग से तय नहीं हो पाने से करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद इस योजना पर पानी फिर रहा है।

(दै.भा., 06.10.12)

वार्षिक योजना की कछुआ चाल

राज्य की अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक योजना का हाल यह है कि एक अप्रेल से लेकर 31 अक्टूबर तक सात महीनों में सिर्फ 38 फीसदी राशि ही खर्च हो पाई है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष से भी दो प्रतिशत कम है। योजना राशि के खर्च के मामले में यह 10 वर्षों का सबसे धीमा प्रदर्शन माना जा रहा है। इस साल की योजना का आकार करीब 33 हजार 141 करोड़ रुपए है, लेकिन सिर्फ 12 हजार 878 करोड़ रुपए के काम ही हो सके हैं।

खर्च की इस गति का अंजाम यह होगा कि अगले तीन माह में राशि खर्च करने के लिए सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए जाएंगे। यह हाल तो तब है जबकि राज्य के मुख्य सचिव सी.के. मैथ्यू बजट घोषणाओं व वार्षिक योजना की राशि को समय पर पूरा खर्च करने के बारे में पिछले सात महीनों में 20 से भी ज्यादा बैठकें ले चुके हैं। कई विभागों को चेताया भी गया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। *(रा.प., 15.12.12)*

लाल बत्ती गाड़ी का सफर करोड़ों बकाया

राजनीतिक नियुक्ति पाकर बोर्ड निगमों के अध्यक्ष बने कई नेता लाल बत्ती लगी गाड़ियों का आनन्द तो उठा रहे हैं, लेकिन सरकार को उनका पैसा नहीं चुका रहे। इन पर सरकारी गाड़ियों के पेटे एक करोड़ 14 लाख 51 हजार 975 रुपए बकाया है। सरकार का मोटर गैराज विभाग इन नेताओं से न तो पैसा वसूल पा रहा है और न ही गाड़ियां वापस ले पा रहा है।

विभाग ने भविष्य में होने वाली ऑडिट आपत्ति से बचने के लिए अब मामला मंत्री मुरारी लाल मीणा और मुख्य सचिव सी.के. मैथ्यू के पास भेज दिया है। ताकि या तो गाड़ियां वापस आएं या बकाया पैसा जमा हो सके। *(रा.प., 18.11.12)*

केन्द्र सरकार ने नहीं दिए 3400 करोड़

केन्द्र और राजस्थान में भले ही कांग्रेस की सरकारें हैं लेकिन राज्य के हिस्से के 3409 करोड़ रुपए काफी समय से केन्द्र सरकार ने अटका रखे हैं। 2007-08 से 2011-12 के दौरान कई योजनाओं के पेटे मिलने वाली इस राशि को हासिल करने के लिए राजस्थान लगातार प्रयासरत है लेकिन अभी तक भी कामयाबी नहीं मिल रही।

यह राशि है बकाया: राज्य में वैट लागू होने के बाद सीएसटी के पेटे होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए राज्य को मिलने वाले 1184.42 करोड़ रुपए, कृषि ऋणों की माफी योजना के तहत 115 करोड़, 2009 में आपदा राहत में 600 करोड़, ग्यारहवें वित्त आयोग की राशि में से 359.39 करोड़, यूआईडीएसएसएमटी के तहत 420.01 करोड़, 12 नगर पालिकाओं की डीपीआर के लिए पुनर्भरण राशि के रूप में 2.07 करोड़ तथा लेवी चीनी समानीकरण कोष के तहत एफसीआई को देने के लिए 15.25 करोड़। *(रा.प., 14.10.12)*

खादी के नाम पर खुली लूट

राज्य सरकार की स्फूर्ति योजना के तहत जयपुर स्थित लोकसेवा संस्थान खादी ग्रामोद्योग की ओर से खादी कलस्टर बस्सी से जुड़ी संस्था फागी द्वारा सूती एवं पोली के लिए निःशुल्क चरखे व करघे कातिनों को वितरित किए जाने थे। इनसे होने वाले उत्पाद को संस्थान द्वारा खरीद कर बेचा जाना था।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इस योजना में लाखों रुपए की गड़बड़ी पकड़ी है। ब्यूरो द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ कि बुनकरों को यह चरखे बांटे ही नहीं गए। जो चरखे व करघे बांटे गए उनके भी पैसे वसूल लिए गए। उन चरखों से फर्जी उत्पादन दिखाया गया। दूसरी जगहों से माल खरीदा गया और उसे बेच कर व फर्जी बिल लगाकर कई प्रकार से धांधलियां की गई। *(रा.प.एवं दै.भा., 19.10.12)*

मनरेगा में घटे काम मांगने वाले

प्रदेश में मनरेगा योजना में 100 दिन काम मांगने वाले परिवारों की संख्या घट रही है। चार साल पहले 26 लाख परिवारों ने 100 दिन का काम मांगा था, जबकि इस साल छह महीने बीतने के बाद 77 हजार लोगों ने ही काम मांगा है।

हाल यह है कि अनुसूचित जाति बाहुल्य होने के आधार पर नरेगा के पहले चरण में स्थान पाने वाले करौली व सिरोही जिले में ही इस साल गिनती के परिवारों को काम मिला है। राज्य का ग्रामीण विकास विभाग काम मांग पर आधारित होने का तर्क देकर गिरती संख्या पर जवाब देने से पल्ला झाड़ रहा है। *(रा.प., 21.10.12)*

बेकार गए 368 करोड़ रुपए

राज्य सरकार ने 2007-08 से लेकर 2011-12 के बीच विकास कार्यों, पुराने कर्जों के पुर्नभुगतान तथा ब्याज के भुगतान के लिए भारत सरकार, वित्तीय संस्थाओं और जनता से कर्ज लिया, लेकिन कर्ज का पूरा इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। इस दौरान सरकार को करीब 368 करोड़ 74 लाख रुपए का बतौर ब्याज अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।

इसका खुलासा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए पेश की गई कैग की रिपोर्ट में किया गया है। सरकार ने इन वर्षों में करीब 28522.76 करोड़ रुपए का जनता से कर्जा लिया। इसमें से करीब 1287 करोड़ की राशि अनुपयोगी रही, इसके अलावा करीब 93 करोड़ रुपए सरकार ने ट्रेजरी बिलों के निवेश के माध्यम से कमाए, लेकिन इस पर ब्याज सहित 1656 करोड़ रुपए सरकार को चुकाने पड़े।

रिपोर्ट के अनुसार सरकार की ओर से वर्ष 2007-08 में 80.52 करोड़, 2008-09 में 93.62 करोड़, 2009-10 में 83.66 करोड़, 2010-11ऽ में 42.03 करोड़ तथा 2011-12 में 68.91 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा, जो सरकार पर एक चपत की तरह है। *(रा.प., 15.10.12)*

बच्चों का हलवा खा गए अफसर

सीकर जिले के एक लाख 34 हजार बच्चों के पोषाहार के लिए भेजी गई हलवा, पंजीरी और उपमा बनाने की सामग्री अफ़सर ही हजम कर गए। महिला एंव बाल विकास विभाग द्वारा भेजे गए इस सामान की कीमत दो करोड़ सात लाख रुपए है। इसे आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 6 साल तक के बच्चों को परोसा जाना था। इस खाद्य सामग्री का वजन 4305 क्विंटल है।

फिलहाल अनियमितता उजागर होने के बाद विभाग ने सम्बन्धित अफसरों को नोटिस थमा दिए हैं। अन्य कई जिलों में भी पोषाहार गायब होने का अंदेशा है। सीकर जिले में पोषाहार के गायब होने की पुष्ठि हो गई है। यह गड़बड़ी ऑडिट रिपोर्ट में पकड़ी गई। सीकर जिले के महिला और बाल विकास विभाग के उपनिदेशक का कहना है कि पोषाहार गायब नहीं बल्कि अवधिपार होने के कारण नष्ट कर दिया गया था। प्रश्न है अवधिपार यह सामग्री कहां से और क्यों पहुंची। *(दै.भा., 25.11.12)*

घटती जा रही है विधान सभा की बैठकें

भले ही विधानसभा अध्यक्षों के कई सम्मेलनों में सालाना 60 बैठकों पर सहमति बनी हो, विधान सभा की बैठकें लगातार घटती जा रही है। 13वीं विधानसभा के अब तक के सत्रों में तो कम बैठकों का रिकॉर्ड कायम हो गया है। इन चार सालों में विधानसभा की अधिकतम सालाना 27 बैठक हुई हैं। रिकॉर्ड देखे तो मौजूदा स्पीकर दीपेन्द्र सिंह शेखावत के कार्यकाल में चार साल में महज 97 बैठकें हुई, जबकि पिछली विधान सभा में तत्कालीन स्पीकर सुमित्रा सिंह के चार साल के कार्यकाल में 111 बैठकें हुई थी।

जयपुर में पिछले साल विधान सभा के भीतर जुटे देशभर की विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में सहमति भी बनी लेकिन फिर भी बैठकें घट गई। पिछले साल विधानसभा की बैठक घटने की शिकायत राष्ट्रपति भवन तक पहुंची लेकिन कोई सुधार नहीं आया। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप का मानना है कि तब तक जनता दबाव नहीं बनाएगी इसी तरह मूल्यों को तिलांजलि दी जाती रहेगी। *(रा.प., 04.12.12)*

भगवान का पैसा खर्च कर रहे हैं अफसर

मन्दिरों में भगवान के चढ़ावे में आने वाले करोड़ों रुपए देवस्थान विभाग के अफसर मनमाने तरीके से खर्च कर रहे हैं। इस राशि से अफसर न केवल अपनी गाड़ियों में पेट्रोल-डीजल भरवा रहे हैं बल्कि ऑफिस फर्नीचर, कम्प्यूटर, एसी तक खरीद रहे हैं। नियमानुसार यह राशि भगवान के भोग, पोषाक, उत्सव, पुजारियों के वेतन व मन्दिर के जीर्णोद्धार पर खर्च की जा सकती है।

कानूनी रूप से भगवान को नाबालिग माना गया है, इसलिए इस राशि का कोई दूसरा उपयोग नहीं किया जा सकता। जबकि विभाग के अफसर इस खर्च को सही ठहराने के लिए राजस्थान देवस्थान निधि बजट व लेखा नियम 1997 का हवाला दे रहे है। विधि विभाग का कहना है कि सरकार ने इस तरह के कोई नियम ही नहीं बना रखे हैं। वित्त विभाग की ओर से देवस्थान विभाग जयपुर के सहायक आयुक्त प्रथम व द्वितीय के कार्यालयों की विशेष ऑडिट कराई गई, जिसमें एक करोड़ रुपए से भी ज्यादा की अनियमितता सामने आई है। *(दै.भा., 19.11.12)*

बिना नियमों के चल रहा टैक्स बोर्ड

राजस्थान टैक्स बोर्ड 18 साल से बिना नियम कायदों के ही चल रहा है। इस अवधि में हजारों मुकदमों का निस्तारण हो गया, हजारों अभी लंबित हैं। जोधपुर व उदयपुर में टैक्स बोर्ड की सर्किट बैंच भी चलाई जा रही है। राजस्थान टैक्स बोर्ड सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट जैसी न्यायिक संस्थाओं की श्रेणी में आता है, जिसमें राज्य के कर संबंधी मामलों की सुनवाई होती है।

न्यायिक कार्य करने वाली हरेक संस्था की कार्यप्रणाली नियमों से विनियमित होती है। पूर्व में यह विक्रय कर अधिकरण के रूप में काम कर रहा था, लेकिन 1995 में इसे राजस्थान टैक्स बोर्ड का नाम व दर्जा तो दे दिया लेकिन संचालन के नियम कायदे नहीं बनाए गए। अब 18 साल बाद इसकी सुध ली गई है। *(दै.भा., 10.10.12)*

शहरी विकास योजना में अनियमितता

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन में अनियमितताओं को लेकर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कैग) ने राजस्थान, मध्यप्रदेश समेत कई राज्य सरकारों की खिंचाई की। कैग ने निराशा जताई कि पहले चरण की मिशन की अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। राज्यसभा में पेश कैग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सीटू-विकास अजमेर-पुष्कर शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं के तहत 3437 आवासीय इकाइयों का निर्माण होना था। इसकी मंजूरी 2006-07 में मिल गई थी लेकिन परियोजना पर अभी भी काम चल रहा है।

जोधपुर में एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम के तहत परियोजना के दूसरे चरण में चार मामलों में ठेकेदारों को 43.19 लाख की निविदा प्रीमियम की मंजूरी दी गई जिसे अनियमित रूप से परियोजना लागत के नाम में डाल दिया गया। *(रा.प., 30.11.12)*

सरकार को लगी 30 करोड़ की चपत

राज्य सरकार को पिछले 5 सालों में 30 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान हुआ है। इनमें 9 करोड़ रुपए की अनियमितताएं और 20.74 करोड़ रुपए स्टाम्प शुल्क वसूली में लापरवाही बरती गई है। कैग की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। विधानसभा में रखी गई इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010-11 के बीच सम्पत्तियों की कीमत कम आंकने और गलत दरें लागू करने में 9.04 करोड़ रुपए की अनियमितताएं की गई है।

जांच में सामने आया है कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अधिकारियों ने यह पता लगाने की जहमत ही नहीं उठाई कि रजिस्ट्री के लिए पेश दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क की गणना सही है या गलत। रिपोर्ट में माना गया है कि जिला पंजीयक एवं उप महानिरीक्षक द्वारा पंजीयक कार्यालयों के नियमित निरीक्षण भी नहीं किए जा रहे। *(रा.प., 12.10.12)*

सांसद निधि में मिलीं गड़बड़ियां

सांसद निधि का पैसा खर्च करने में कई स्तरों पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। सांसद निधि से 1.44 करोड़ रुपए के 61 प्रतिबंधित श्रेणी के निर्माण के काम करवा लिए गए। सांसदों ने सिफारिश करते समय योजना के उद्देश्य और नियमों का ध्यान रखे बिना 5 जिलों में सरकारी दफ्तरों और भवनों के 45 निर्माण कामों की सिफारिशें कर दीं। पांच निजी और वाणिज्यिक निर्माण के कामों पर 18 लाख रुपए की शिफारिशें कर दी गई।

यह खुलासा भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी)के राज्य विधानसभा में रखे गए सिविल रिपोर्ट 2010 में किया गया है। रिपोर्ट में शहरी निकायों, पंचायती राज संस्थाओं और सांसद निधि के खर्च में कई स्तरों पर गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। *(दै.भा., 12.10.12)*

दुष्प्रचार से बिगड़ रही है देश की छवि

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर दुष्प्रचार से देश की छवि बिगड़ रही है। इससे अधिकारियों का मनोबल भी गिर रहा है। यह बात उन्होंने सीबीआई और राज्यों के भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के ज्यादातर बड़े मामले कारोबारी कंपनियों से जुड़े हैं।

उन्होंने कहा पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून में बदलाव किया जाएगा। घूस लेने को ही नहीं बल्कि घूस देने को भी भ्रष्टाचार की परिभाषा के दायरे में लाने के प्रयास करने होंगे। साथ ही भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में आधार कार्ड योजना को मजबूती से लागू किया जाएगा। *(दै.भा., 11.10.12)*

प्राकृतिक संसाधन बने भ्रष्टाचार का अड्डा

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आरएम लोढ़ा ने कहा है कि देश में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अब ये संसाधन भ्रष्टाचार करने के अड्डे बन गए और इनमें करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों में भ्रष्टाचार के कई मुकदमें अदालतों में चल रहे हैं और हर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है।

जयपुर कर सलाहकार संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अपने उक्त विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि देश में 50 फीसदी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत देते हैं। उन्होंने कहा कि सभी जगह भ्रष्टाचार फैल चुका है। सरकारी अफसरों ने भी पद का दुरुपयोग कर इसे बढ़ाया है। इससे हमारा लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। सरकार को चाहिए कि वह ऐसा मजबूत सिस्टम बनाए कि प्राकृतिक संसाधनों में भ्रष्टाचार नहीं हो। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आगामी पीढ़ियां प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकेगी और यह नुकसान हमेशा के लिए हो जाएगा। *(रा.प. एवं दै.भा., 09.12.12)*

भ्रष्टाचार में भारत 94वें पायदान पर

सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सूची में शामिल 176 देशों में भारत 94वें स्थान पर है। पिछले साल 183 देशों में भारत 95 वें स्थान पर था। सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क, फिनलैंड व न्यूजीलैंड सूचकांक में सबसे ऊपर है। इसका मतलब है इन तीनों देशों में सबसे कम भ्रष्टाचार है। इसके बाद चौथे नम्बर पर स्वीडन और पांचवें नम्बर पर सिंगापुर रहे हैं। जर्मनी, जापान और अमेरिका क्रमशः 13, 17 व 19वें स्थान पर हैं।

भारत की स्थिति पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश से बेहतर है। इनको सूची में क्रमशः 139 वां तथा 144वां स्थान मिला है। लेकिन श्रीलंका और चीन से खराब है। सूची में श्री लंका का 79वां और चीन का 80वां स्थान है। म्यामार, सूडान, अफगानिस्तान, उत्तरकोरिया, सोमालिया को सबसे भ्रष्ट देशों में गिना जा सकता है।

(रा.प. एवं दै.भा., 06.12.12)

आधार कार्ड से थमेगा भ्रष्टाचार

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधार से जोड़ने पर राशन की चोरी पर अंकुश लगेगा। आधार कार्डधारी ही राशन सामग्री उठा पाएंगे। इस तरह की प्रणाली तैयार की जाएगी कि आधार कार्डधारी का रिकॉर्ड में पूरा इन्द्राज होगा कि उसने क्या-क्या सामग्री ली है। ऐसे में जो राशन कार्डधारी सामान नहीं उठा पाएंगे, उनके हिस्से के सामान को खुर्दबुर्द नहीं किया जा सकेगा।

राज्य सरकार का मानना है कि अब मनरेगा में भी मजदूरों को फर्जी भुगतान नहीं हो सकेगा। मनरेगा को आधार से जोड़ने के बाद कार्डधारी ही मजदूरी का भुगतान ले सकेगा। इससे भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकेगा। प्रदेश में सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग पहले चरण में आधार से पांच योजनाओं को जोड़ने की कवायद कर रहा है।

(रा.प., 25.10.12)

लोकपाल को संवैधानिक दर्जा मिले

सीबीआई, सीवीसी और लोकपाल को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इससे वे प्रभावी ढ़ंग से काम कर सकेंगे। कैग संवैधानिक संस्था हैं, इसने 2जी, कोल ब्लॉक आवंटन और कॉमनवेल्थ जैसे कई भ्रष्टाचार के मामलों को खुलासा किया है। लोकपाल कानून से भी भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। लेकिन इससे हम भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार रूपी राक्षस का प्रभाव जरूर कम कर सकते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग), विनोद राय ने गुड़गांव में आयोजित विश्व इकॉनोमिक फोरम की बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि ये संस्थाएं सही काम करें तो आपको उन्हें संवैधानिक दर्जा देने का जोखिम उठाना पड़ेगा। कॉरपोरेट समूहों में पारदर्शिता की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। मीडिया और नागरिक समूहों को इसके लिए प्रयास करना चाहिए।

(दै.भा.एवं रा.प., 08.11.12)

कालेधन से देश को हुआ नुकसान

कालेधन से देश को पिछले एक दशक में 123 अरब डॉलर यानि 6.64 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 2001 से 2010 के बीच ऐसा नुकसान उठाने वाला भारत आठवां सबसे बड़ा देश है। अमेरिकी संस्था रिसर्च एवं एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। इसके मुताबिक कालेधन से नुकसान उठाने वाले देशों की टॉप-20 सूची में दक्षिण एशिया से सिर्फ भारत ही शामिल है।

रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2010 में अनियमित वित्तीय प्रवाह से भारतीय अर्थव्यवस्था को 1.6 अरब डालर यानि 87.76 अरब रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के सह लेखक देवकार ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लिए 123 अरब डॉलर का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। इस रकम का निवेश शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में किया जा सकता था। *(दै.भा. एवं रा.प., 19.12.12)*

चार साल में दोगुना हुआ भ्रष्टाचार

पिछले दो साल में तमाम भ्रष्टाचार विरोधी अंदोलनों के बावजूद आम आदमी को भ्रष्टाचार से कोई राहत नहीं मिली है। देश में नौ प्रमुख शहरों में हुए एक अध्ययन के मुताबिक पिछले चार साल में भ्रष्टाचार के मामले दोगुने हो गए हैं। सर्वे में शामिल 60 फीसदी लोगों ने माना है कि पिछले सालभर में भी यह बढ़ा ही है।

सेंटर फॉर मीडिया स्टॅडीज ने यह सर्वे कराया है। यह संस्था वर्ष 2000 से ही देश में भ्रष्टाचार के आंकड़ों का अध्ययन कर रही है। संस्था की ताजा रिपोर्ट 'इंडिया करप्शन स्टॅडी-2012' के नाम से जारी हुई है। इसके मुताबिक मुंबई भ्रष्टाचार के मामले में शीर्ष पर है यहां चार साल में पांच गुना भ्रष्टाचार बढ़ा है। *(दै.भा.एवं न.नु., 08.12.12)*

जागे विरोध करने की समझ

देश भ्रष्टाचार रूपी गुलामी की जंजीरों से जकड़ा है। अरविन्द केजरीवाल का भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन देश के विकास को सही दिशा देने वाला कदम है। आज हर जगह व्याप्त भ्रष्टाचार से आमजन परेशान है। बावजूद इसके विरोध करने की समझ विकसित होने में समय लग रहा है।

केजरीवाल के विरोध के स्वर को सभी ओर से समर्थन मिल रहा है। क्योंकि यह स्वर उनका ही नहीं आम जनता का भी है। लड़ाई आसान नहीं है और इसमें समय भी लगेगा, लेकिन एक दिन सफलता निश्चित है। भ्रष्टाचार रूपी अंधकार मिटेगा, बस सभी को अपने हिस्से की मशाल थामे चलना है। **-अंजू सिंह, जयपुर**

जब्त होगी लोकसेवकों की काली कमाई

भ्रष्ट तरीकों से काली कमाई कर सम्पत्ति बनाने वाले लोकसेवकों की अब खैर नहीं। अब प्रदेश में भ्रष्टाचार के जरिए की गई काली कमाई और उससे बनाई गई सम्पत्ति को जब्त करने का कानून लागू हो गया है। इसके दायरे में सरकार से वेतन लेने वाले चपरासी से लेकर मुख्यमंत्री और न्यायिक अधिकारी तक शामिल होंगे। इसके लिए राज्य विधान सभा ने इसी साल 12 अप्रेल को राजस्थान विशेष न्यायालय बिल पारित किया था और राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भिजवाया था। अब राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने इसका राजपत्र में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। विस्त्रत नियम बनने के बाद यह खुलासा हो सकेगा कि इसके दायरे में पुराने मामले भी आएंगे या नहीं।

विधेयक में यह है मुख्य प्रावधान

- *ऐसे मामलों में फैसला करेगी विशेष कोर्ट।*
- *मुकदमा दर्ज होने पर सम्पत्ति का बेचान व हस्तान्तरण होगा अवैध।*
- *बाजार दर से होगा सम्पत्ति का आकलन।*
- *हाईकोर्ट विशेष परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा तीन महीने का स्टे दे सकेगा।*
- *आरोपी बरी होगा तो आंकी गई सम्पत्ति का मूल्य मय ब्याज के उसे लौटाया जाएगा।*

विधेयक में ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए दो विशेष न्यायालय बनाए जाने का प्रावधान है। ये जयपुर और जोधपुर में खोले जाएंगे। इन न्यायालयों में जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारी होंगे और उनका नियंत्रण हाईकोर्ट के पास रहेगा। *(रा.प. एवं दै.भा.14.12.12)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
झुंझुनूं	सुभाष चन्द्र	एएसआई, बेरी चौकी, पिलानी	2,500	दै.भा., 02.10.12
सीकर	शीशराम राम लाल	पटवारी, हल्का चैनपुरा, सीकर बिचौलिया, निवासी कटराथल, सीकर	20,000	दै.भा., 04.10.12
राजसमंद	राजेन्द्र नुवाल	कार्यालय सहायक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग	10,000	दै.भा., 06.10.12
चित्तौड़गढ़	उगमाराम कुमावत	सरपंच, रघुनाथपुरा पंचायत समिति	4,100	दै.भा., 10.10.12
उदयपुर	शीला तिवारी	परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, झाड़ोल	23,000	रा.प., 20.10.12
भीलवाड़ा	प्रमोद कुमार चतुर्वेदी	एएसआई, हमीरगढ़ थाना, भीलवाड़ा	15,000	दै.भा., 24.10.12
चितौड़गढ़	सुभाष कुमावत तेज राम	निरीक्षक, आयकर विभाग, चित्तौड़गढ़ कर सहायक, आयकर विभाग , चित्तौड़गढ़	6,500	रा.प. एवं दै.भा., 26.10.12
भरतपुर	बलवीर सिंह	सहायक सब इंस्पेक्टर, रुदावल थाना, भरतपुर	3,000	दै.भा., 01.11.12
श्रीगंगानगर	अमीचन्द जाखड़	कनिष्ठ अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम	10,000	रा.प., 17.11.12
जयपुर	मिथिलेश शर्मा	कनिष्ठ लिपिक, परिवहन कार्यालय, जगतपुरा जयपुर	15,000	दै.भा.एवं रा.प., 21.11.12
जयपुर	राजेश स्वामी सुभाष चौधरी	निरीक्षक, परिवहन कार्यालय चौमूं के लिए मध्यस्थ, धर्मकांटा मालिक का बेटा,रेनवाल रोड़	20,000	दै.भा.एवं रा.प., 24.11.12
राजसमन्द	श्रवण कुमार	पूर्व ग्राम सचिव, ग्वार पंचायत समति, कुंभलगढ़	1,500	रा.प., 28.11.12
सीकर	मक्खन मीणा	हैड कॉस्टेबल, श्री माधोपुर थाना, सीकर	1,500	रा.प., 28.11.12
चित्तौड़गढ़	चौथ मल	सहायक उप निरीक्षक, बिनोता पुलिस चौकी इंचार्ज	3,500	दै.भा., 29.11.12
बारां	राधेश्याम गुर्जर	कॉस्टेबल, बिलेंडी चौकी, छीपाबड़ौद	2,000	दै.भा., 01.12.12
करौली	महेन्द्र सिंह जाट	वन रक्षक, वन रेंज हिंडौन	2,000	दै.भा., 03.12.12
जयपुर	सुरेश यादव	कॉस्टेबल, सीआईडी सीबी, पुलिस लाइन, जयपुर	30,000	रा.प., 07.12.12
प्रतापगढ़	हरि नारायण प्रजापत	सचिव, टामटिया ग्राम पंचायत	34,000	रा.प., 08.12.12
हनुमानगढ़	मंगल सिंह भींवा राम	सहायक उप निरीक्षक, नोहर पुलिस थाना आरएसी जवान, नोहर पुलिस थाना	6,000	रा.प.., 08.12.12
जालोर	जगदीश राम विश्नोई	सब इंस्पेक्टर, भीनमाल थाना जालौर	5,000	दै.भा., 10.12.12

संसद का सही तरीके से चलना जरूरी

हाल ही हंगामे के कारण ठप रही संसद के बाबत राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने अहम सुझाव देते हुए कहा है कि संसद के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम में बदलाव करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के लिए बनाई गई संसदीय समितियों को बजट आवंटन की स्वीकृति के बाद उनकी गहनता से जांच करनी चाहिए। आज देश का बजट लाखों करोड़ों रुपए का हो गया है, ऐसे में धन और वित्त की व्यवस्था के लिए लोकसभा में प्रतिनिधियों द्वारा और अधिक समय दिया जाए।

उन्होंने कहा कि कई बार सांसद छोटे-छोटे मुद्दों पर भड़क जाते हैं। इससे संसदीय कार्य में बाधा आती है। सासदों को सामूहिक रूप से विकास के रास्ते में आने वाली बाधाएं चाहे वो कानूनी हो या प्रशासनिक उन्हें दूर करना चाहिए, ताकि गरीबों को इसका लाभ मिल सके। *(दै.भा., 14.10.12)*

पार्टियों को मिले धन की हो ऑडिट

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरेशी ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले धन तथा अनुदान की सालाना अनिवार्य ऑडिट का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाला सारा धन पारदर्शी और जांचा गया होना चाहिए।

उन्होंने नई दिल्ली में कामनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेनेजमेन्ट के सम्मेलन के अवसर पर सभी राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने का भी समर्थन किया है। उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की आवश्यकता जताते हुए कहा कि पार्टियां कंपनियों से धन पाती हैं और बाद में उन्हें लाभान्वित भी करती हैं। *(रा.प., 25.10.11)*

ग्रामीण विकास के लिए नई योजना

राज्यों को ग्रामीण विकास में मदद करने के लिए केन्द्र सरकार पहली बार 40 हजार करोड़ रुपए का एक लचीला कोष तैयार करने की योजना बना रही है। यह कोष राज्यों के लिए अगले साल से 12वीं पंचवर्षीय योजना के आखिर तक के लिए उपलब्ध रहेगा। इस कोष में केन्द्र सरकार की 70 फीसदी हिस्सेदारी होगी।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्यों के लिए यह कोष अतिरिक्त राशि के रूप में उपलब्ध रहेगा। इस कोष से ग्रामीण विकास मंत्रालय की मौजूदा योजनाओं या केन्द्रीय पेयजल और स्वच्छता योजनाओं पर खर्च किया जा सकेगा। कोष स्थापित करने की इस योजना को मंजूरी के लिए मंत्रीमंडल के समक्ष रखा जाएगा। *(न.नु., 19.10.12)*

गांव-गांव दौड़ेगी रोडवेज बस

गांवों तक आने जाने के साधनों की कमी और उससे ग्रामीणों को हो रही परेशानी के मद्देनजर राज्य सरकार ने गांव-गांव तक रोडवेज बस पहुंचाने के लिए ग्रामीण परिवहन सेवा शुरू की है। यातायात और परिवहन मंत्री वीरेन्द्र बेनीवाल ने बताया कि इस सेवा के तहत उन मार्गों पर भी बसें चलाई जाएगी, जहां घाटे के चलते वाहन नहीं चलाए जाते।

इस सेवा से 2000 बसें चलाई जाएंगी और राज्य की चार हजार पंचायतों को जोड़ा जाएगा। जिन रूटों पर घाटा होगा, उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि बसों का किराया रोडवेज तय करेगा। *(रा.प., 13.12.12)*

अब मनरेगा में होगा एपीएल का भी बीमा

राज्य में बीपीएल मनरेगा मजदूरों को मिल रही चिकित्सा बीमा सुविधा अब एपीएल मजदूरों को भी मिलेगी। जयपुर सहित सात जिलों अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर व जोधपुर में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। फरवरी से पूरे राज्य में मनरेगा कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। केन्द्र सरकार से इस बारे में सहमति मिल गई है। केन्द्र सरकार ने नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी को यह जिम्मेदारी सौंपी है।

कम्पनी ने फरवरी से 18 जिलों में योजना लागू करने की तैयारी कर ली है। सात जिलों के लिए बीमा की जिम्मेदारी एलएण्डटी कम्पनी को दी गई है। बीमा कम्पनियां रजिस्टर्ड मजदूर को साल में 30 हजार रुपए तक की मदद करेगी। *(रा.प., 11.12.12)*

संपत्ति की असल कीमत नहीं छिपा सकेंगे

अखिल भारतीय सेवा और राज्य सरकार के अफसर अब चाहते हुए भी अपनी संपत्ति की असल कीमत नहीं छुपा पाएंगे। यह संभव होगा उस कानून से, जो भ्रष्टाचार की कमाई जब्त करने के मकसद से हाल में लागू किया गया है। अभी तक ज्यादातर अफसर अपनी संपत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य के बजाय खरीद मूल्य बता रहे थे।

सभी अधिकारियों को वर्ष 2012 के लिए 31 जनवरी 2013 तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा घोषित करना है। इसके चलते कई ने अपनी संपत्ति का मूल्यांकन करवाना शुरू कर दिया है। *(दै.भा., 20.12.12)*

सहरिया परिवारों को मुफ्त तेल-दाल

राज्य सरकार बारां जिले के 22 हजार 373 सहरिया परिवारों को हर महीने 2 किलो दाल और 5 किलो तेल मुफ्त देगी। पहले चरण में दिसम्बर से मार्च, 2013 तक हर परिवार को यह दाल व तेल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद इसे पूरे साल के लिए लागू करने की योजना है।

सरकार ने यह निर्णय सहरिया परिवारों में व्याप्त कुपोषण के मद्देनजर लिया है। इस पर पहले चार महीनों में सरकार पर 9 करोड़ 60 लाख रुपए का खर्च आयेगा और यह उचित मूल्य की दुकानों के जरिए दिया जाएगा। *(दै.भा., 13.12.12)*

नहीं आना आरटीआई के दायरे में

कोई भी राजनीतिक दल सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के दायरे में नहीं आना चाहते हैं। इन दलों ने केन्द्रीय सूचना आयोग में सुनवाई के दौरान इसका विरोध किया है। पार्टियों का कहना है उनके कार्यालयों के लिए इमारतें व अन्य सुविधाएं सरकार की आर्थिक मदद के दायरे में नहीं आती।

मुख्य सूचना आयुक्त सतेन्द्र मिश्रा और सूचना आयुक्त अन्नपूर्णा दीक्षित व एमएल शर्मा की पीठ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉम की उस अपील की सुनवाई कर रही थी जिसमें राजनीतिक दलों को आरटीआई एक्ट के दायरे में लाने की बात कही गई थी। *(रा.प., 03.11.12)*

मरीजों की सामान्य जांचें होंगी मुफ्त

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवाओं के बाद अब मरीजों की जांचें भी मुफ्त किए जाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह जानकारी देते हुए यह घोषणा की है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस अर्थात 7 अप्रेल, 2013 से सभी मेडिकल कॉलेजों व इनसे संबद्ध अस्पतालों और जिला अस्पतालों में सामान्य जांचे जैसे खून की जांचें, शुगर, संक्रमण, लिवर, किड़नी, हृदय, कोलेस्ट्रोल, ईसीजी व यूरीन टैस्ट आदि मुफ्त में होंगी।

अगले चरण में इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी लागू किया जाएगा। फिलहाल मरीजों को एमआरआई, सोनोग्राफी, सीटी स्केन जैसी महंगी जांचें पैसे देकर करानी होगी। योजना के आगे बढ़ने पर यह भी मुफ्त की जा सकती हैं। *(रा.प.एवं दै.भा., 14.12.12)*

बिजली पर सरकार देगी सब्सिडी

बिजली दरों में बढ़ोतरी का भार सभी उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। 50 लाख यूनिट से कम बिजली का उपभोग करने वाले, बीपीएल कनेक्शन व कृषि कनेक्शन वाले करीब एक करोड़ उपभोक्ताओं को सरकार सब्सिडी देगी। इससे एक करोड़ एक लाख बिजली उपभोक्ताओं में से बिजली की बढ़ी दरों का बोझ केवल एक लाख उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा।

ऊर्जा मंत्री जितेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि शेष एक करोड़ उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार 2550 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। यह राशि राज्य सरकार हर साल विद्युत निगम को मुहैया करा देगी। प्रदेश के किसानों को रबी सीजन में लगातार छह घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से पूरे इन्तजाम किए जा चुके हैं। *(दै.भा., 01.12.12, 07.12.12)*

उचित मूल्य पर मिलेगी बिजली

प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह ने कहा है कि सरकार देश के सभी नागरिकों को सामान्य दर पर विद्युत उपलब्धता आगामी पांच साल के दौरान सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों के दौरान एक लाख से भी ज्यादा गांवों को बिजली सुलभ कराई गई है।

भारतीय उद्योग परिसंघ व अक्षय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को खाना पकाने की गैस उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। ग्रामीण परिवारों को विद्युत और गैस के लिए अनुदान भी देना होगा।

उन्होंने कहा कि भारत की कुल विद्युत क्षमता में सोलर पॉवर की हिस्सेदारी 12 फीसदी हो गई है। वर्ष 2022 तक देश के परिवारों को सोलर पॉवर से विद्युत आपूर्ति सम्भव हो सकेगी। देश में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता को वर्ष 2017 तक बढ़ाकर 55 गीगावॉट करने का निर्णय लिया गया है। *(न.नु., 14.10.12)*

महंगे नहीं होंगे कृषि कनेक्शन

नए बिजली कनेक्शन लेने वाले किसानों को कनेक्शन वर्तमान दर पर ही मिलेगा। इसके लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति ने फैसला कर वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। अभी किसानों को एक हॉर्स पावर का कनेक्शन 2500 रुपए की डिमांड शुल्क पर दिया जाता है। बिजली कंपनियां बढ़ते खर्च व महंगाई के चलते इस राशि को बढ़ाना चाहती है।

अब सरकार बिजली कंपनियों को ज्यादा सहायता देगी, लेकिन किसानों से वसूली जाने वाले शुल्क में बढ़ोत्तरी नहीं करेगी। अगले साल करीब 40 हजार कनेक्शन दिए जाने हैं। सरकार कंपनियों को एक कृषि कनेक्शन पर 30 प्रतिशत राशि की सहायता देती थी, अब 50 फीसदी सहायता देगी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2008 में आवेदन कर चुके सभी किसानों को डिमांड नोटिस जारी करने के लिए कम्पनियों को निर्देश दिए हैं।

(रा.प., 17.10.12, 10.11.12)

शिकायत सुनवाई के लिए नई चौखट

जयपुर डिस्कॉम में कनेक्शनों पर बिजली चोरी, भारी भरकम बिल, एवरेज के नाम पर ज्यादा बिल, सिक्यूरिटी के नाम पर ज्यादा बिल एवं अन्य गड़बड़ियों के मामले में की गई कार्रवाई से असंतुष्ट उपभोक्ताओं की अपील की सुनवाई अब तीसरा पक्ष करेगा।

अब तक ऐसे मामलों में कार्रवाई करने वाली बिजली कंपनी को ही उपभोक्ताओं से संबंधित कार्रवाई के विरोध में अपील सुनने का भी अधिकार था। इससे जिस कंपनी के खिलाफ अपील, उसी कंपनी को सुनवाई का अधिकार होने से निष्पक्ष कार्रवाई को लेकर सन्देह बना रहता था। अब राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने सुनवाई का अधिकार कंपनियों के हाथों से छीन कर राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम को सौंप दिया है। *(दै.भा., 06.12.12)*

प्रदेश में दो नए बिजलीघर तैयार

झालावाड़ में कालीसिंध व बारां जिले के छबड़ा में बन रहे बिजलीघरों में से दो इकाइयां इसी साल में तैयार हो जाएगी। लेकिन बिजलीघर तक कोयला पहुंचना फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि रेलवे ट्रैक का काम अभी अधूरा है। इससे कालीसिंध तक कोयला पहुंचाने में देरी हो सकती है। राज्य उत्पादन निगम ट्रकों से कोयला लाकर इस इकाई को चलाने की योजना बना रहा है।

छबड़ा बिजलीघर में तैयार हो रही तीसरी इकाई से 250 मेगावाट की क्षमता से बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। यहां पहली व दूसरी इकाई पहले से चल रही है, इससे कोयला मिलने में दिक्कत नहीं है। अनुमान है कि मार्च, 2013 से इस इकाई से बिजली मिलना शुरू हो जाएगा। कालीसिंध इकाई से बिजली उत्पादन में कुछ माह और इंतजार करना पड़ेगा। *(रा.प., 12.12.12)*

बिजली कंपनियों की बिगड़ती हालत

राज्य की तीनों बिजली वितरण कंपनियों का घाटा थमता नहीं दिख रहा। दो बार बिजली की दरें बढ़ाने के बाद भी अगले साल मार्च तक यह घाटा 50 हजार करोड़ पहुंचने का अनुमान है। जानकारों की माने तो कम्पनियों की कंगाली बढ़ाने में खुद राज्य सरकार की लुभावनी योजनाओं का बड़ा हाथ हैं। बिजली कम्पनियों का पहले हर साल 10 हजार करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था। दरें बढ़ने से यह घटकर सालाना करीब सात हजार करोड़ रह गया है।

बिजली कंपनियों ने अब तीसरी बार बिजली दरें बढ़ाने के लिए राज्य विनियामक आयोग में याचिका लगा रखी है। लेकिन इसके बाद भी कंपनियां घाटे से नहीं उबर पाएंगी। असल में कंपनियों के घाटे की जड़ राज्य सरकार की योजनाएं हैं। पिछले चार सालों में किसानों की बिजली दरों के अनुदान पेटे सरकार ने कंपनियों को 4396 करोड़ रुपए ही दिए। जबकि कपनियों को इससे कई गुना ज्यादा कीमत पर बिजली खरीदनी पड़ी। *(रा.प., 15.12.12, 24.12.12)*

बिजली कंपनी की मनमानी

आर्थिक तंगी से जूझ रही जयपुर विद्युत वितरण कंपनी मनमानी पर उतर आई है। उपभोक्ताओं पर दो से तीन साल का बकाया बताते हुए दो से 10 हजार रुपए तक की अमानत राशि जमा कराने के नोटिस थमाए जा रहे हैं। राशि जमा नहीं कराने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी जा रही है। बिजली कंपनी ने दिसम्बर के अंत तक शहर के सभी 6.80 लाख उपभोक्ताओं से प्रतिभूति राशि लेने का फैसला किया है।

बिजली कंपनी का कहना है कि उपभोक्ताओं को वर्तमान बिल के आधार पर अमानत राशि जमा कराना अनिवार्य है। पहले उनका बिल कम आता था अब बिजली की दरें बढ़ने व ज्यादा उपभोग करने से बिजली बिल ज्यादा आता है। इसलिए अन्तर राशि की वसूली की जा रही है। जबकि उपभोक्ताओं का कहना है कि दो-तीन साल पहले जमा करवाई गई राशि की रसीद वे कहां ढूंढें? *(दै.भा., 01.10.12)*

बिजली छीजत, बिजली चोरी ! उपभोक्ता पर है दोनों भारी !!

देश में 30 फीसदी बचा भूजल भंडार

वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि भारत में सिर्फ 30 फीसदी भूजल भंडार बचा हुआ है। अभी सचेत नहीं हुए तो अगले 20 साल में यह भंडार खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा। यह चेतावनी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आयोजित 5वें विश्व भूजल सम्मेलन में जुटे वैज्ञानिकों ने दी।

सम्मेलन में भाग ले रहे तमिलनाडू कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मलियास्वामी ने बताया कि भारत में भूजल दोहन का अनुपात दुनिया के मुकाबले तिगुना हो गया है। लेकिन पुनर्भरण का अनुपात बहुत कम है। सोलापुर यूनिवर्सिटी के डॉ. पी. प्रभाकर ने कहा देश में जल पुनर्भरण की दर 0.5 फीसदी है। इसलिए बारिश के मौसम के अलावा अन्य मौसमों में पानी की किल्लत रहती है। *(दै.भा., 19.12.12)*

वैज्ञानिकों ने बताए यह उपाय

- भूजल उपयोग के बारे में कठोर कानून बने।
- भूजल उपयोग पर पैसे वसूले जाएं।
- एक बस्ती में बोरवेल की संख्या पर नियंत्रण हो।
- जल पुनर्भरण अनिवार्य हो।
- भूजल के सही इस्तेमाल की शिक्षा प्राथमिक स्तर से अनिवार्य हो।
- तटों पर बसे शहर समुद्र का पानी शुद्ध कर इस्तेमाल करें।

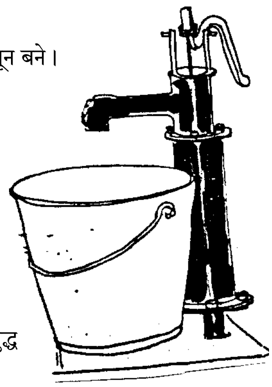

फ्लोराइड रहित पानी के लिए योजना

प्रदेश में फ्लोराइड रहित पानी के लिए 2938 करोड़ रुपए की पेयजल योजना लागू होगी। खासतौर से नागौर व बीकानेर जिलों के लिए इस योजना में जापान की एजेंसी जायका 2199 करोड़ रुपए का सहयोग देगी।

इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल परियोजना का हिस्सा 339 करोड़ रुपए और राज्य सरकार का 400 करोड़ रुपए होगा। इस साल से शुरू हो रही यह परियोजना 2016-17 तक पूरी होगी।

फ्लोराइड के कारण दांतों और हड्डियों में फ्लोरोसिस की बीमारियां खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। इसी को देखते हुए केन्द्र सरकार ने नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस के तहत नागौर जिले का चयन किया था। जिले में पहले चरण का काम पूरा हो गया है और दूसरे चरण में जिले के 7 कस्बों और 978 गांवों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही बीकानेर जिले के दो कस्बों और 111 गांवों को शामिल किया जाना प्रस्तावित है। *(दै.भा., 15.10.12)*

पानी में यूरेनियम बना घातक जहर

प्रदेश के कई जिलों के भूजल में खतरनाक यूरेनियम पाया गया है। सीकर में तो इसकी मात्रा तय मानक से सौ गुना तक अधिक मिली है। विशेषज्ञों के अनुसार लगातार अधिक यूरेनियम युक्त पानी पीने से कैंसर का खतरा होता है।

यह खुलासा हाल ही परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय की ओर से किए अध्ययन में हुआ है। यह अध्ययन रिमोट एरिया में हुआ है, जबकि यह समस्या आबादी वाले क्षेत्रों में भी है। प्रदेश के नागौर के डीडवाना और सिंही तालाब, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली और सीकर जिले के दौराला में यूरेनियम की मात्रा अधिक मिली है। गौरतलब यह है कि अब तक प्रदेश में सरकारी स्तर पर इस समस्या के प्रति कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई है। *(रा.प., 29.12.12)*

बहुत दुरुपयोग हो रहा है पानी का

भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से जयपुर में वाटर कॉनक्लेव 2012 आयोजित किया गया। इस सेमिनार में खासतौर पर यह उभर कर सामने आया कि देश में पानी का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। पानी की जो कुल खपत है उसका 80 फीसदी खेती में हो रहा है, उद्योगों मे 13 प्रतिशत और घरेलू खपत केवल 7 प्रतिशत है।

खेती में जा रहे पानी का दो तिहाई से भी अधिक अर्थात 70 फीसदी पानी का कोई अधिक उत्पादक उपयोग नहीं हो रहा। पीने के पानी की तंगी अब भी देश के अनेक शहरों, कस्बों व गांवों में है।

पानी की कमी का देश में बिजली उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ा है। खेती में पानी का वैज्ञानिक नीति से कम उपयोग किया जाकर अधिक उत्पादन किया जाना जरूरी है। बरसात के पानी का संरक्षण करने, उपयोग में जागरूकता लाकर और सही प्रबंधन से सुधार लाया जा सकता है। *(न.नु., 06.12.12)*

बेकार बह जाता है पीने का पानी

रोजाना 2.5 लाख लोगों के पीने का पानी व्यर्थ बह जाता है जिससे जलदाय विभाग को कोई आय नहीं हो रही। प्रतिदिन 1276 लाख लीटर पानी छीजत में चला जाता है। जिसका खर्चा विभाग को वहन करना पड़ता है। इसमें करीब 380 लाख लीटर पानी तो लीकेज के जरिए सड़कों पर बेकार बह जाता है।

जलदाय विभाग के अनुसार रोजाना 32 फीसदी पानी की छीजत होती है। अगर विभाग इस 32 फीसदी पानी की छीजत रोक ले तो इससे 8.5 लाख लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है। विभाग करीब 7 फीसदी पानी लीकेज में बहना स्वीकारता है, जबकि विशेषज्ञों के अनुसार यह 10-12 फीसदी है। जयपुर शहर में रोजाना 3800 लाख लीटर पानी सप्लाई होता है। जिसके हिसाब से रोजाना 1276 लाख लीटर पानी छीजत में चला जाता है। *(रा.प., 12.11.12)*

पानी पिया लेकिन दाम चुकाना भूले

जयपुर में 3.5 लाख जल उपभोक्ताओं में से करीब 80 हजार ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने सालों से पानी के बिलों का भुगतान नहीं किया। इसमें सरकारी विभाग और निजी उपभोक्ता शामिल हैं। इनमें करीब 16 करोड़ रुपए बकाया हैं। कई उपभोक्ता ऐसे भी है जिन्होंने पानी के बिल की बकाया राशि जमा कराने से बचने के लिए नया कनेक्शन ले लिया।

यह ही नहीं जयपुर विकास प्राधिकरण व नगर निगम सहित केन्द्र व राज्य सरकार के कई कार्यालय 1.34 करोड़ रुपए का पानी पी गए, लेकिन जलदाय विभाग को पानी का भुगतान करना मुनासिब नहीं समझा।

जलदाय विभाग ने पानी का बिल नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं व सरकारी कार्यालयों को नोटिस जारी करना शुरू किया है। इन उपभोक्ताओं से बकाया राशि वसूलने के लिए उनकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। *(दै.भा., 15.10.12, रा.प., 16.10.12)*

राष्ट्रीय जल नीति पहली प्राथमिकता

जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने कहा है कि राज्यों के साथ समन्वय कर राष्ट्रीय जल नीति का कार्यान्वयन उनकी मुख्य प्राथमिकता होगी। साथ ही पर्यावरण व दूसरी वजहों से जिन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में देर हो रही है उनमें तेजी लाई जाएगी।

जल संसाधन मंत्री का कार्यभार ग्रहण करते हुए उन्होंने कहा कि वे ऐसा तंत्र विकसित करने की कोशिश करेंगे, जिसके जरिए समयबद्ध तरीके से मुद्दों का समाधान किया जा सके।

यह सुनिश्चित करने के लिए जहां भी जरूरी होगा कानून बनाया जाएगा। नदियों को जोड़ने के मुद्दे पर रावत ने कहा कि वे विभिन्न राज्यों से इस संबंध में आए प्रस्तावों पर विचार करेंगे। *(न.नु., 31.10.12)*

जमीनी स्तर तक जागा पूरा देश

वर्ष 2012 जाते-जाते पूरे देश को जगा गया। दिल्ली में हुई 23 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म की बर्बर घटना ने संसद से लेकर जमीनी स्तर तक सभी को अन्दोलित कर दिया। देश में जहां देखो वहां महिलाएं या पुरुष हो अथवा छात्र समुदाय बिना किसी के उकसाए सड़कों पर आ गए। सभी ने अपराधियों को फांसी जैसा कठोरतम दंड देने की मांग की। आम जन की यह मांग वाजिब है। देश की सरकार ने एक बार तो आन्दोलन को कुचलने का मानस बनाया। कई नेता ऊल-जलूल बयान भी देने लगे। लेकिन ऐसी अमानवीय हरकत पर आमजन का जो गुस्सा भड़का, उसके आगे अन्ततः सरकार नतमस्तक दिखने लगी।

देश की राजधानी से लेकर आन्दोलन गांवों की चौपालों तक जा पहुंचा। स्थिति के मद्देनजर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम महाअभियान के ऐजेंडे को लागू करेंगे और राज्य स्तर पर सख्त कानून लाएंगे। विपक्ष ने भी आम जन के साथ होने की स्वीकारोक्ति की। देश के गृहमंत्री ने भी इसे कबूल तो किया लेकिन फांसी शब्द का जिक्र नहीं किया। लोगों का मानना है कि अगर पुलिस, सरकार, अदालत और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर ठान ले तो ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है।

अब जनता ने तय कर लिया है कि जब तक ऐसे अपराधियों के लिए फांसी जैसा कठोर दंड का प्रावधान नहीं होगा, तब तक जन अभियान किसी भी हालत में ठंडा नहीं होगा।

पढ़ाएंगे भ्रूण हत्या व दहेज विरोधी पाठ

कन्या भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा के दुष्परिणामों को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार ने पीसीपीएनडीटी एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए दायर एक याचिका को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को यह विश्वास दिलाया। अदालत में राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता आर.पी.सिंह ने कहा कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम में इन मुद्दों को शामिल किया जाएगा।

इससे पूर्व हाईकोर्ट ने भ्रूण हत्या व दहेज रोकने के विचारों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने को कहा था। साथ ही कहा था कि स्कूलों के जरिए अंतिम संस्कार में बेटियों को प्रोत्साहन, सिर्फ बेटी होने पर मां-बाप को पेंशन व शादियों में फिजूलखर्ची रोकने के सुझावों को भी अमल में लाया जाए।

(रा.प.एवं दै.भा., 02.11.12)

योजनाओं में हो तालमेल - राज्यपाल

प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में बच्चों और महिलाओं को लेकर चल रही योजनाओं व कार्यक्रमों में ओवरलैपिंग के चलते धन व समय के अनावश्यक खर्च को राज्यपाल मारग्रेट अल्वा ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने एक ही तरीके के काम अलग-अलग विभागों के बजाय एक ही विभाग के सुपुर्द करने की मंशा जताई है।

इस सिलसिले में वे तीन विभागों महिला व बाल विकास, सामाजिक न्याय, व अधिकारिता और समाज कल्याण बोर्ड की साझा बैठक लेंगी। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तीनों विभागों के आला अधिकारी और मंत्री भी रहेंगे। उत्तराखंड में राज्यपाल रहने के दौरान उन्होंने वहां भी तीनों विभागों में तालमेल बनाया था। अब वही पहल राजस्थान में भी करना चाहती हैं।

(दै.भा., 17.12.12)

प्रसवकाल में जान गंवाती महिलाएं

गरीबी, भुखमरी, कुपोषण और आर्थिक कुप्रबंधन के कारण प्रसव के दौरान भारत में हर दस मिनट में एक मां को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 में प्रसव के दौरान देश में 57 हजार माताओं की मौत हुई है। यह आंकड़ा शर्मसार करने वाला है। साथ ही यह भी प्रमाणित करता है कि देश में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं बदतर स्थिति में हैं।

'सेव द चिल्ड्रन' संस्था की सालाना रिपोर्ट वर्ल्डस मदर्स-2012 में कहा गया है कि मां बनने के लिहाज से भारत खराब देशों में शुमार है। इस बारे में 80 विकासशील देशों में भारत 76 वें स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की निष्क्रियता और उदासीनता की वजह से बुनियादी स्वास्थ्य स्थिति नाजुक बनी हुई है।

(रा.स., 31.10.12)

महिला उत्पीड़न पर विशेष कोर्ट

महिला उत्पीड़न मामलों की सुनवाई के लिए प्रदेश में संभाग स्तर पर विशेष कोर्ट खोलने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। गृह विभाग ने पांच नई कोर्ट खोलने का प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा है। इसे जल्द हाईकोर्ट को भेजा जाएगा।

प्रस्ताव में जयपुर और कोटा में चल रही महिला उत्पीड़न निवारण संबंधी विशेष कोर्ट को संभाग स्तरीय माना गया है। भीलवाड़ा और गंगानगर की विशेष कोर्ट को संभाग स्तरीय मानने के बारे में स्पष्टीकरण चाहा गया है।

यह भी कहा गया है कि जिन पांच संभाग मुख्यालयों पर महिला उत्पीड़न निवारण संबंधी विशेष कोर्ट नहीं हैं, वहां विशेष कोर्ट खोलने के लिए आवश्यक सुविधाओं के बारे में हाईकोर्ट से पूछा जाए। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने हाल ही में इन नई कोर्ट के लिए घोषणा की थी।

(रा.प., 29.12.12)

महिलाओं के लिए ज्ञान केन्द्र की स्थापना

सरकार की नीति और फैसलों के बारे में सबसे पहले गांव की महिलाओं को जानकारी मिलेगी। इसके लिए मोबाइल, वेब और सामुदायिक रेडियो का इस्तेमाल किया जाएगा। सयुंक्त राष्ट्र महिला संगठन ने इसकी पहल की है। योजना पर अमल के लिए जयपुर में ज्ञान केन्द्र की स्थापना की गई है।

यह केन्द्र महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न राजनीतिक, प्रशासनिक, विधिक व सामाजिक मसलों पर परामर्श देगा। महिलाएं मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकेंगी। राजस्थान में फिलहाल टोंक, डूंगरपुर और अलवर जिलों को इससे जोड़ा गया है।

(दै.भा., 05.10.12)

दुष्कर्म के रोजाना पांच मामले

राजस्थान पुलिस भले ही प्रदेश में कानून व्यवस्था के मजबूत होने के दावे करती हो, लेकिन वस्तुस्थिति कुछ और है। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में रोज पांच महिलाएं दुष्कर्म का शिकार हो रही है। रोजाना नौ जनों का अपहरण हो रहा है, जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक रहती है।

प्रदेश में गत तीन वर्षों के मुकाबले तीन फीसदी अपराधिक वारदातें अधिक दर्ज की गई हैं। वहीं, दो वर्ष का आंकड़ा करीब छह फीसदी बढ़ा है। इसमें महिलाओं से संबंधित अपराध की बढ़ोतरी दो वर्ष में 17 फीसदी रही।

हालांकि हत्या व हत्या के प्रयास के मामले इस साल कम दर्ज हुए हैं, लेकिन इस साल चोरी के करीब 22 हजार मामले दर्ज हुए जो गत वर्ष से दो हजार ज्यादा है।

(रा.प., 27.12.12)

सड़क सुरक्षा

अब पैदल भी सुरक्षित नहीं – प्रदीप महता

पिछले दिनों वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव वी.एस.सिंह पैदल सड़क पार करते हुए हादसे का शिकार हुए। उनके निधन पर गहरा शोक जताते हुए कट्स के महामंत्री और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् के सदस्य प्रदीप एस.महता ने कहा है कि राज्य सरकार अभी भी आम जन को सुरक्षित सड़कें उपलब्ध कराने में विफल रही है। जबकि सरकार सुरक्षित सड़कें बनवाने व उनका विकास करने के नाम पर हर साल तीन हजार करोड़ रुपए खर्च करने का दावा करती है।

उनका यह भी कहना है कि सड़क पर पैदल चलने वाले कुल जनसंख्या का 49 प्रतिशत हिस्सा है और वो भी सड़कों पर चलने से डरने लगे हैं। राज्य सरकार कई सालों से सड़क सुरक्षा नीति बनाने की बात ही करती रही है।

राजस्थान देश में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं वाले राज्यों की प्रथम पांच की सूची में है। यह तो तब हो रहा है, जब केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हमारे राज्य से हैं और प्रदेश उन गिने चुने राज्यों में है जहां राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा परिषद स्थापित है। उपरोक्त सभी तथ्यों के मद्देनजर राज्य सरकार को विचार करना होगा कि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो भविष्य का अंजाम क्या होगा ?

यह है हालात

- *शहर की सड़क पर औसतन रोज एक आदमी अकाल मौत का शिकार हो रहा है।*
- *कहीं रोड इंजीनियरिंग की खामी है तो कहीं लापरवाह वाहन चालक। शहरी क्षेत्र में तीन सालों में इसी तरह 1200 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।*
- *अकाल मौत का शिकार होने वालों में हर तीसरा व्यक्ति पैदल होता है।*
- *शहर में 11 माह में 360 लोग मौत के शिकार हुए, इनमें से 110 ऐसे थे जो या तो सड़क पार कर रहे थे या सड़क के किनारे चल रहे थे।*
- *प्रदेश की सड़कों पर आठ माह में 6133 लोग जान गंवा चुके हैं।*
- *पिछले साल 9232 लोग दुर्घटना के शिकार हुए थे, जिसमें जयपुर के 1302 लोग थे।*

जन स्वास्थ्य

सस्ती होंगी 348 जरूरी दवाएं

केन्द्र सरकार के आदेश है कि दवाइयां अब ब्रांड के नाम से नहीं बल्कि जेनरिक नाम से मिलेंगी। केन्द्र की ओर से यह आदेश सभी राज्य सरकारों को भेजे गये हैं। राज्य के औषधि नियंत्रक संगठन ने आदेश मिलने पर ब्रांड विशेष के नाम से लाइसेन्स देना बन्द कर दिया है। इससे मरीजों के आर्थिक शोषण से मुक्ति मिलेगी।

इसके अलावा केन्द्रीय केबिनेट ने राष्ट्रीय दवा मूल्य नीति को भी मंजूरी दे दी है। इससे 348 जरूरी दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इस नीति को केबिनेट ने इस मकसद से मंजूरी दी है कि दवाओं की कीमतें तय करने के लिए नियामक ढ़ांचा तैयार किया जाए ताकि उन्हें उचित कीमत पर मुहैया कराना सुनिश्चित किया जा सके।

नई नीति के मुताबिक सभी ब्रांड्स की औसत कीमत निकाल कर उसे अधिकतम कीमत घोषित किया जाएगा । सरकार का कहना है कि इस फैसले से आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। पिछले 10 साल में दवाओं की कीमतों में जबर्दस्त इजाफा हुआ है। इससे दवाओं की बेतहाशा बढ़ती कीमतों की रफ्तार थमेगी। *(रा.प. एवं दै.भा., 18.10.12, 23.11.12)*

केन्द्र चलाएगा निःशुल्क दवा योजना

प्रदेश में चल रही निःशुल्क दवा योजना और जल्द शुरू होने वाली निःशुल्क जांच योजना को आगामी साल में नई दिशा मिल सकती है। केन्द्र ने सभी राज्यों के एनआरएचएम प्रशासन को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन(एनआरएचएम)की कार्य योजना में इसे शामिल करने के निर्देश दिए हैं। राज्य संभावनाओं के हिसाब से इसे एनआरएचएम में शामिल करने का प्रस्ताव भेज सकते हैं। राजस्थान में फिलहाल राज्य सरकार निःशुल्क दवा योजना चला रही है और निःशुल्क जांच योजना भी लाई जा रही है। यदि प्रदेश में इसे एनआरएचएम के तहत शामिल कर लिया जाता है तो राज्य सरकार को करीब 500 करोड़ रुपए के खर्च से राहत मिलेगी। *(रा.प., 18.12.12)*

पर्यावरण

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान

राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित

हमारा देश जैव विविधता के क्षेत्र में एक सम्पन्न राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, इथजिसका मानवीय हस्तक्षेप और बड़े पैमाने पर हो रहे दोहन से लगातार ह्रास होता जा रहा है। सभी को जैव विविधता के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व को समझते हुए इसके संरक्षण के प्रयास करने होंगे।

राजस्थान राज्य जैव विविधता संरक्षण बोर्ड के प्रबन्धक अशोक पारीक ने कट्स द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से रोटेरी क्लब, जयपुर में आयोजित ङजैव विविधता संरक्षण' विषयक राज्य स्तरीय कार्यशाला में यह बात कही। उन्होंने जैव विविधता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वर्तमान में जैव विविधता संरक्षण बोर्ड पंचायत स्तर पर बायोडायवर्सिटी कमेटी का गठन कर रहा है, जिसमें स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग अपेक्षित है।

कार्यक्रम में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए जॉर्ज चेरियन, निदेशक, कट्स ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैव विविधता के संरक्षण के मकसद से 2011 से 2020 को जैव विविधता दशक घोषित किया है। इसके संरक्षण के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को अभियान के माध्यम से लोगों में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करना होगा।

अभियान प्रभारी धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ने बताया कि इस अभियान के तहत राज्य की 200 से अधिक स्वयंसेवी संस्थाएं अपने-अपने क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियां सचालित करेंगी। यह अभियान पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 से चलाया जा रहा है। कट्स वर्ष 2006-07 से रीजनल रिसोर्स ऐजेन्सी के तौर पर इस अभियान को संचालित कर रहा है। कार्यशाला में अमरदीप सिंह वरिष्ठ परियोजना अधिकारी ने सभी प्रतिभागियों को विषय की जानकारी देते हुए अभियान के तहत की जाने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया।

नष्ट हो रही है जैव विविधता

सामाजिक संगठनों ने आगाह किया है कि देश की आर्थिक नीतियां जैव विविधता और आजीविका को बड़े पैमाने पर नष्ट कर रही है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हिस्सा ले रहे 25 से भी ज्यादा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि आर्थिक विकास की यह अंधी दौड़ आगे चलकर बहुत महंगी साबित होगी।

संगठनों के अनुसार तेजी से बढ़ रहे औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की नीतियों के कारण भूमि, वन, नदियां, पहाड़, समुद्री तट और घास के मैदान कम अथवा नष्ट होते जा रहे हैं । इससे न केवल जीवजन्तुओं की संख्या घटती जा रही है बल्कि गरीबों की आजीविका पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। *(न.दु., 12.10.12)*

उपभोक्ता फैसले

टिकट बुक होने पर भी सीट नहीं देना रेलवे को महंगा पड़ा

जयपुर स्थित जगतपुरा रोड निवासी सुरेश चन्द मीणा व इन्द्रा बाजार के रामकिशोर शर्मा ने भारतीय रेलवे के खिलाफ उपभोक्ता मंच, जयपुर प्रथम में अलग-अलग परिवाद दायर किया। उन्होंने मंच को बताया कि रेलवे ने एक यात्री की सहायता करने के आशय से आरक्षण चार्ट में उनके नाम को काटकर उस पर हाथ से अन्य व्यक्तियों के नाम लिख, उन्हें सीट आवंटित कर दी। रेलवे अधिकारियों से उन्होंने जब इसकी शिकायत की तो उनकी सुनवाई तक नहीं की गई। आखिर उन्हें खड़े होकर यात्रा करनी पड़ी।

मामले की सुनवाई पर मंच ने प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पाया कि रेलवे ने चार्ट में हाथ से नाम लिखकर अन्य व्यक्तियों को सीट आरक्षित की थी। मंच ने रेलवे को टिकट बुक होने पर भी सीट नहीं देने का दोषी माना। मंच ने भारतीय रेलवे के अध्यक्ष, उप रेलवे जयपुर मंडल के प्रबंधक और पश्चिमी रेलवे भोपाल मंडल के प्रबन्धक को संयुक्त या पृथक रूप से सुरेश चन्द मीणा एवं रामकिशोर शर्मा को दस-दस हजार रुपए मानसिक संताप की एवज में हर्जाना देने और डेढ़-डेढ़ हजार रुपए परिवाद खर्च के तौर पर अदा करने के आदेश दिए हैं। *(रा.प., 13.11.12)*

हाउसिंह बोर्ड को भारी पड़ा सुविधाएं दिए बिना पार्किंग शुल्क वसूलना

करुणा बोहरा और ज्ञान सिंह ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ उपभोक्ता मंच, जयपुर में अलग अलग मामले दर्ज कराए। अपने-अपने परिवाद में उन्होंने मंच को बताया कि बोर्ड की स्ववित्त पोषित योजना 2007 के तहत प्रताप नगर स्थित मेवाड अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदे थे। बोर्ड पार्किंग के लिए छोड़ी गई खुली जगह पर पार्किंग के एवज में बिना कोई सुविधाएं दिए शुल्क वसूल नहीं कर सकता। लेकिन बोर्ड उनसे यह शुल्क वसूल कर रहा है।

सुनवाई पर मंच ने बोर्ड द्वारा की गई इस वसूली को गलत ठहराया। मंच ने करुणा बोहरा के मामले में पार्किंग शुल्क के रूप में वसूली राशि 57 हजार 495 रुपए मय 12 फीसदी ब्याज सहित वापस लौटाने के निर्देश दिए। साथ ही, 30 जून 2011 से सुविधाएं देने तक जमा राशि 23 लाख 38 हजार 784 रुपए पर 10 फीसदी की दर से ब्याज देने और 50 हजार रुपए हर्जाने के रूप में अदा करने के भी आदेश दिए हैं।

इसी तरह मंच ने ज्ञान सिंह के मामले में भी 97 हजार 225 रुपए मय 12 फीसदी ब्याज सहित वापस लौटाने, जमा राशि 19 लाख 86 हजार 215 रुपए पर सुविधाएं मुहैया कराने तक 10 फीसदी ब्याज देने तथा 50 हजार रुपए बतौर हर्जाना अदा करने के आदेश दिए हैं। *(दै.भा., 11.12.12)*

खास समाचार

मिलावट की तो देना होगा जुर्माना और टांगना होगा बोर्ड

भीलवाड़ा जिले के मिलावट करते पकड़े गए दो दुकानदारों को एक साल तक दुकान के बाहर 2 गुना 3 फीट का बोर्ड लगाना होगा।

इस बोर्ड पर लिखा होगा – **'मैं मिलावटखोर हूं'**

जन हित के मद्देनजर यह अनूठी सजा भीलवाड़ा जिले की एडीएम कोर्ट ने दी है। इसके अलावा कोर्ट ने इन दोनों पर एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उन्हें बोर्ड पर जुर्माना लगने की सूचना भी लिखनी होगी। भीलवाड़ा में बाजार नं. 3 स्थित रामा स्वीट्स की दुकान पर मिलावटी मावा और कृषि उपज मंडी के पास स्थित शक्ति वारदाना भंडार के यहां मिलावटी तेल पाए जाने के मामले में जिले की एडीएम कोर्ट ने यह आदेश दिए। दोनों दुकानदारों पर दो-दो मामले बनाए गए थे।

व्यापारियों ने कोर्ट में सब स्टैंडर्ड सामान बेचने की गलती मानी। कोर्ट ने रामा स्वीट के सुवालाल शर्मा पर दस हजार रुपए तथा शक्ति वारदाना भंडार के राकेश कुमार अग्रवाल पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह राशि उन्हें एक माह के भीतर कोर्ट में जमा करानी होगी।

उम्मीद की जाती है कि कोर्ट के इस फैसला से मिलावटखोरों में डर पैदा होगा। कोर्ट के इस फैसले को एक नजीर के रूप में भी देखा जा सकता है। *(दै.भा., 31.10.12)*

सहमति के बिना नहीं होती मिलावट

जयपुर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में मिलावट पर चिंता जाहिर करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि राज्य में अधिकारियों की खामी की वजह से ही खाद्य वस्तुओं मे मिलावट हो रही है। क्योंकि, उनकी मूक सहमति के बिना कोई भी मिलावट नहीं कर सकता। यदि अधिकारियों के साथ नेता और व्यापारी ईमानदारी से काम करें तो मिलावट पर अंकुश लगाया जा सकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि खाद्य वस्तुओं में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई करने का काम अब चिकित्सा विभाग को दिया गया है। अब चिकित्सा विभाग अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसमें और अधिक पारदर्शिता लाने की जरूरत है। मिलावट के खिलाफ उपभोक्ताओं को भी जागरूक होना चाहिए। खाद्य पदार्थों में मिलावट या किसी तरह की गड़बड़ी की आंशका होने पर उन्हें विभाग में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। *(दै.भा., 25.12.12)*

बने उपभोक्ता संरक्षण के नियम

करीब 10 साल पहले केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून में संशोधन किया था। इसके बाद राज्य सरकार को जरूरत के माफिक इसके नियम बनाने थे। यह नियम अब जाकर बन पाए हैं। लेकिन अभी राज्य सरकार ने इन्हें लागू नहीं किया है, सिर्फ इनका मसौदा तैयार कर, जनता की राय जानने के लिए सार्वजनिक किया गया है।

प्रारूप में उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सदस्य संख्या 56 से घटा कर 50 कर दी गई है। इसमें भी दस सदस्य केन्द्र सरकार मनोनीत करेगी। उम्मीद की जाती है कि नियम जल्द ही जारी होंगे। इससे अब राज्य व जिला स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का नए सिरे से गठन होगा और उपभोक्ता मंचों में खाली पदों पर नियुक्तियां हो सकेंगी। *(रा.प., 06.10.12)*

स्त्रोत: रा. प.: राजस्थान पत्रिका, दै. भा.: दैनिक भास्कर, न. नु.: नफा नुकसान, दै. न.: दैनिक नवज्योति, रा.स.: राष्ट्रीय सहारा

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोन: 91.141.513 3259 फैक्स: 228 2485, टेलीफैक्स: 401 5395, ई-मेल: cart@cuts.org, वेबसाईट: www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।